ISSN: 2395-7852

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management

Volume 10, Issue 1, January 2023

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 7.421

+91 9940572462 +91 9940572462 ijarasem@gmail.com www.ijarasem.com

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 7.421| Peer Reviewed & Referred Journal |

| Volume 10, Issue 1, January 2023 |

पाकिस्तान में आर्थिक संकट: एक विश्लेषण

Dr. Dhiraj Bakolia

Associate Professor, Dept. of Political Science, Govt. Lohia College, Churu, Rajasthan, India

सार

पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इस हालात से उबरने के लिए वो दुनियाभर में भीख मांग रहा है। 2022 पाकिस्तान के लिए गंभीर चुनौतियों वाला साल साबित हो सकता है। विश्लेषक अब चेतावनी दे रहे हैं कि पाकिस्तान (Pakistan) कभी भी दिवालिया हो सकता है। रिपोर्टों से पता चला है कि 9,000 से अधिक कंटेनर विभिन्न पाकिस्तानी बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं। जिससे आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित होने का खतरा है। देश में महंगाई दर करीब 30 फीसदी तक पहुंच गई है। इसके अलावा खाद्य वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। हालात ये हैं कि बंदरगाहों में फंसे कंटेनरों की निकासी नहीं कर पा रही है। शिपिंग कंपनियां समय पर भुगतान ना करने की वजह से पाकिस्तान के संचालन को निलंबित करने की धमकी दे रही हैं। अगर ऐसा होता है तो इससे आयात और निर्यात दोनों पर बुरा असर पड़ेगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) के पास विदेशी मुद्रा भंडार में केवल 4.4 बिलियन डॉलर रह गया है जो मुश्किल से तीन सप्ताह के लिए पर्याप्त है। वहीं, कंटेनरों को खाली करने के लिए लगभग डेढ़ से दो बिलियन डॉलर की आवश्यकता है। आपूर्ति श्रृंखलाओं के टूटने के कारण पाकिस्तान में कारोबार बंद होने का खतरा है क्योंकि घरेलू स्तर पर निर्मित सामान आयातित कच्चे माल पर ही निर्भर हैं। पाकिस्तान में कपड़ा उद्योग भी गंभीर स्थिति में है। ये उद्योग अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के बीच विश्वसनीयता और बाजार हिस्सेदारी खो रहा है। इसके अलावा, पाकिस्तान के अस्पतालों में दवाओं की कमी हो रही है। वहीं, जल्द ही गेहूं, खाद और पेट्रोल जैसी चीजें भी खत्म हो सकती हैं। इस बीच, प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने लोगों से अपने आयात बिल को कम करने में सरकार की सहायता के लिए पानी, गैस और बिजली जैसे संसाधनों का संरक्षण करने के लिए कहा है। बता दें कि शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान सरकार कर्ज पाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की सभी शर्तों को पूरा करने पर सहमत हो गई है। शरीफ ने 24 जनवरी को कहा था कि पाकिस्तान का सत्तारूढ़ गठबंधन पैसे के लिए आईएमएफ की कड़ी शर्तों को स्वीकार करके देश की खातिर अपने राजनीतिक करियर का त्याग करने के लिए तैयार है।

परिचय

गौरतलब है कि पाकिस्तान के पूर्व सीनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने हाल ही में कहा था कि पाकिस्तान राजनीतिक और नैतिक रूप से दिवालिया हो गया है। खोखर ने केटा में राष्ट्रीय संवाद के दूसरे सत्र को संबोधित करते हुए कहा था कि आज भी लोगों को वो सच नहीं बताया जा रहा है जिसकी देश को जरूरत है। [1]सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के पूर्व नेता ने ये भी कहा कि देश के लोगों और राजनीतिक दलों के बीच संपर्क टूट गया है। पनामा पेपर्स और तोशखाना मामले जैसे अप्रासंगिक राजनीतिक प्रवचनों में लगे रहने के बजाय लोगों के मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था (Pakistan Economy) अपने बुरे दौर से गुजर रही है. पाकिस्तान के सामने अब हुकूमत या शासन-प्रशासन का संकट नहीं है, बल्कि इस वक़्त वो राज्यसत्ता से जुड़ी दुश्वारियों से जूझ रहा है. इस बार पाकिस्तानी राज्यसत्ता के वजूद पर ख़तरा मंडरा रहा है. सियासी ठहराव, प्रशासनिक दुर्बलता और क़ाबू से बाहर होते सुरक्षा हालातों के मिले-जुले असर से वहां तयशुदा आर्थिक बर्बादी तेज़ी से पांव पसार रही है. पूरा मुल्क गंभीर मुसीबतों के मकड़जाल में उलझ गया है. अगर किसी के पास इससे निपटने का कोई रोडमैप होता, किसी तरह की योजना होती तो देश को इस जंजाल से बाहर निकाला जा सकता था. बहरहाल सबके पास आधी-अधूरी योजनाएं हैं और वो एक तरह से 'असंभव चमत्कार की आस' लगाए हुए हैं. सबका ध्यान महज़ तात्कालिक संकट (यानी ऋण चुकाने में विफलता) पर टिका हुआ है. [2]लोग आस लगाए हुए हैं और इस बात की दुआ कर रहे हैं कि एक बार कर्ज़ चुकाने में नाकामी का संकट टल जाने से सबकुछ अपने-आप ही ठीक हो जाएगा. 'नए सिरे से पाकिस्तान की कल्पना' करने वाले दिखावटी नसीहतों की कोई कमी नहीं है. हालांकि इन नुस्ख़ों में आम क़िस्म की बातें ही भरी पड़ी हैं. दरअसल अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ख़ास तरह की नीतियों और प्रशासनिक क़दमों (निर्माणकारी ढांचे) की दरकार है. पाकिस्तान को एक सतत, टिकाऊ और व्यावहारिक राज्यसत्ता बनाने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसी कोई योजना दूर-दूर तक दिखाई नहीं दे रही है. पाकिस्तानियों को ऐसा लग रहा है कि अगर वो एकजुट होकर कोई आम राय बना लेते हैं तो वो एक ठोस योजना के साथ सामने आ सकते हैं. हालांकि इस कड़ी में वो एक अहम बात नहीं समझ रहे हैं. दरअसल, सर्वसम्मति तो किसी योजना को लेकर बनाई जा सकती है, सर्वसम्मति के इर्द-गिर्द कोई योजना तैयार नहीं की जा सकती. फ़िलहाल पाकिस्तान के लोग अपने बदतर हालात को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं. वो ये भी नहीं देखना चाहते कि आख़िर किन वजहों से

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 7.421| Peer Reviewed & Referred Journal |

| Volume 10, Issue 1, January 2023 |

उनकी ऐसी दुर्गति हुई है. इससे भी बदतर बात ये है कि वो अब भी इस गफ़लत में हैं कि कोई ना कोई उन्हें बचा लेगा. उन्हें लगता है दुनिया उनकी बदहाली का बोझ नहीं सह सकती, लिहाज़ा उनके दोस्त उन्हें बचा लेंगे या कम से कम उनका वजूद बनाए रखेंगे.[3]

विचार-विमर्श

अदायगी में नाकामी को सिर्फ़ टाला जा सकता है (ज़्यादा से ज़्यादा कुछ महीनों तक या अगर वो क़िस्मतवाले रहे तो एक साल या कुछ अधिक), उसे रोका नहीं जा सकता. हालात कितने विकट हैं, इसे समझने के लिए पाकिस्तान के राजकोषीय गणित पर नज़र डालते हैं. वित्त वर्ष 2022 के बजट में संघीय सरकार का शुद्ध राजस्व 5.03 खरब पाकिस्तानी रुपए रहने का अनुमान लगाया गया था. इस पूरे साल के लिए कर्ज़ पर अदा की जाने वाली ब्याज़ की रकम 3.95 खरब पाकिस्तानी रु है. बहरहाल ब्याज़ दरों में 300 बेसिस अंकों की बढ़ोतरी के चलते ब्याज़ अदायगी का नया अनुमान 5.2 खरब पाकिस्तानी रु हो गया है. दूसरे शब्दों में संघीय सरकार का पूरा राजस्व, कर्ज़ का ब्याज़ चुकाने में ख़र्च हो जाने के बावजूद रकम पूरी नहीं पड़ेगी. बाक़ी की तमाम क़वायदों- प्रतिरक्षा, सरकार चलाना, विकास से जुड़े ख़र्चे आदि को पूरा करने के लिए और ज़्यादा ऋण लिए जाएंगे. बिजली की दरों, ईंधन की क़ीमतों और करों में बढ़ोतरी के साथ-साथ पाकिस्तानी रुपए में गिरावट के चलते आगे हालात और बिगड़ने वाले हैं. कुछ अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि इन उपायों के नतीजतन पाकिस्तान में मुद्रास्फीति की दर 35-40 प्रतिशत तक पहुंच सकती है.[4] इससे ब्याज़ दरों में और बढ़ोतरी करने का दबाव बनेगा, जिसके चलते ऋण पर ब्याज़ अदायगी का बोझ और बढ़ जाएगा. साफ़ तौर से ऐसे हालात कतई टिकाऊ नहीं हैं और इनसे निपटने के लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा. पिछले 25 सालों से पाकिस्तान का कर्ज़ क़रीब-क़रीब हर पांचवें साल दोगुना होता जा रहा है. 1999 में सैन्य तानाशाह द्वारा सत्ता हड़पे जाने के पहले तक पाकिस्तान का कुल ऋण 3.06 खरब पाकिस्तानी रुपए था. 2008 में जनरल मुशर्रफ़ की सत्ता से बेदख़ली और PPP सरकार के हुकूमत संभालते वक़्त ये कर्ज़ 6.7 खरब पाकिस्तानी रुपए तक जा पहुंचा था. 2013 में जब PML सरकार सत्ता में आई तबतक ऋण से जुड़ा ये आंकड़ा 16.3 खरब पाकिस्तानी रुपए को छू चुका था. 2018 में PMLN की सरकार सत्ता से विदा लेते वक़्त PTI की सरकार के लिए 29.8 खरब रु का कुल कर्ज़ छोड़कर गई थी. महज़ चार सालों में PTI सरकार ने इस कर्ज़ को दोगुने से भी ज़्यादा (62.5 खरब पाकिस्तानी रुपए) बढ़ा दिया.[5] हालांकि इस पूरे कालखंड में आर्थिक विकास की प्रक्रिया बेदम रही. इस दौरान कर्ज़ में औसतन तक़रीबन 14 प्रतिशत सालाना की बढ़ोतरी होती रही, लेकिन GDP में महज़ 3 प्रतिशत के आस-पास ही बढ़त दर्ज की जाती रही. बहरहाल, यही वो वक़्त था जब 9/11 हमलों के बाद कर्ज़ के व्यापक पुनर्निर्धारण के रूप में पाकिस्तान को ज़बरदस्त मुनाफ़ा हुआ था. हालांकि पाकिस्तान ने इस मौक़े को गंवा दिया और अर्थव्यवस्था को व्यावहारिक बनाने के लिए ज़रूरी ढांचागत सुधारों पर कोई अमल नहीं हुआ. आर्थिक विकास की लड़खड़ाती रफ़्तार के बीच ऋण पर ब्याज़ चुकाने की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए राजस्व नाकाफ़ी साबित हुआ. चूंकि राजस्व तेज़ी से नहीं बढ़ रहे थे, लिहाज़ा तब की सरकारों को अपने ख़र्चे पूरे करने के लिए और ज़्यादा कर्ज़ लेने पर मजबूर होना पड़ा. नतीजतन पाकिस्तान पूरे होशोहवाश में कर्ज़ के मकड़जाल में फंसता चला गया.[6]

परिणाम

बाद की तमाम सरकारों के कारनामों के चलते अर्थव्यवस्था की लुढ़कती चाल बदस्तूर जारी रही. अब हालात क़ाबू से बाहर हो गए हैं, लिहाज़ा आगे और ढिलाई बरते जाने की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है. अब केवल एक ही विकल्प है हालात से जूझना और ठोस क़वायदों का बोझ उठाना; हालांकि ये कहना जितना आसान है करना उतना ही मुश्किल. [7]इसके लिए बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन की दरकार होगी, बिल्कुल शून्य से इसका निर्माण करना होगा. सरकारी अनुदानों पर ज़िंदा अकार्यकुशल कंपनियों को बंद करना होगा. साथ ही समाज के संभ्रांत तबक़े के लिए सब्सिडियों और मुफ़्त की रेवड़ियों में भारी कटौती करनी होगी. अर्थव्यवस्था के वैसे क्षेत्र जिनपर अब तक टैक्स नहीं लगाए गए हैं या काफ़ी कम टैक्स लगे हैं, उन्हें कर के दायरे में लाना होगा. विशेष हित समूहों (उद्योगपतियों, सेना से जुड़े उपक्रमों, ज़मींदारों आदि) को दी गई रियायतों और हर तरह की छूट को तत्काल बंद करना होगा. राज्यसत्ता को ठेके पर काम कराने की प्रथा शुरू करनी होगी. कई मंत्रालयों में ताले लगाने होंगे, और आख़िरकार सबसे बड़ी चुनौती यानी भारी-भरकम रक्षा बजट में कटौती करनी होगी. इसके अलावा फ़ौज का आकार भी घटाना होगा. साफ़ है कि पाकिस्तान को व्यावहारिक राज्यसत्ता बनाने की क़वायद बेहद मुश्किल है. ये एक ऐसी चुनौती है जिससे हर कोई जब तक मुमकिन हो, बचने या परहेज़ करने की कोशिश करेगा. तात्कालिक संदर्भ में पाकिस्तान का पूरा ज़ोर किसी भी तरह अपना वजूद बचाए रखने के संघर्ष पर होना चाहिए. व्यावहारिक तौर पर पाकिस्तान तंगहाली में डूबा हुआ है, और अर्थव्यवस्था की सांसें बड़ी मुश्किल से चल रही हैं.[8] सब बस यही उम्मीद लगाए हैं कि तकलीफ़ों भरा ये वक़्त किसी तरह गुज़र जाए. हालांकि बदहाली से बचना दिनोंदिन मुश्किल होता जा रहा है. देश का विदेशी मुद्रा भंडार 3 अरब अमेरिकी डॉलर से नीचे आ गया है, जिससे महज़ 2 हफ़्तों के आयात का ख़र्च भी बमुश्किल पूरा हो सकता है. पाकिस्तानी रुपए की हालत लचर हो गई है और खुले बाज़ार में एक डॉलर के बदले 283 पाकिस्तानी रुपए देने पड़ रहे हैं. काला बाज़ार में एक डॉलर, 290 पाकिस्तानी रुपए में मिल रहा है. विदेशों से आयात नहीं आने के चलते देश की आपूर्ति श्रृंखला ठप हो चुकी है. कई उद्योगों में उत्पादन बंद पड़ा है. हाल ही में आए सैलाब से कपास की फ़सल तबाह हो चुकी

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 7.421| Peer Reviewed & Referred Journal |

| Volume 10, Issue 1, January 2023 |

है. ऐसे में पाकिस्तान के सामने कपास का आयात करने की भारी ज़रूरत आ गई है ताकि देश के सबसे बड़े निर्यात (सूती कपड़े) पर असर न हो. हालांकि कपास के आयात के लिए विदेशी मुद्रा है ही नहीं. उधर, कोई भी पाकिस्तान को रकम उधार देने को तैयार नहीं है- ना तो कोई बैंक और ना ही उसके 'दोस्त' (यहां तक कि उसका सदाबहार साथी और सबसे बड़ा कर्ज़दाता चीन भी नहीं).[9] पाकिस्तान के बॉन्ड्स डिफ़ॉल्ट दरों पर कारोबार कर रहे है. ख़बरों के मुताबिक अगले कुछ हफ़्तों में ईंधनों की सप्लाई रुक जाएगी. टेलीकॉम कंपनियों ने भी आगाह कर दिया है कि उपकरणों का आयात करने में नाकामी की वजह से उनकी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं. इन तमाम बिंदुओं पर और ज़्यादा ढोल पीटे बग़ैर इतना कहना ही काफ़ी है कि पाकिस्तान में हर मुमकिन तरीक़े का संकट दिखाई दे रहा है.

पाकिस्तान को पता है कि दिवालिएपन से बचने के लिए उसके पास अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के पैरों पर गिरने के अलावा कोई चारा नहीं है. बहरहाल, IMF ऐसे सुधारों की मांग कर रहा है जिससे पाकिस्तानियों की हालत पतली हुई जा रही है. उन्हें अब भी लगता है कि वो IMF से कुछ रियायतें हासिल कर लेंगे. हालांकि पहली बार IMF अपनी शर्तों पर अड़ा है और कम से कम अब तक किसी भी तरह की रियायत देने को तैयार नहीं हुआ है. इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान लगातार IMF को जताई गई प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करता रहा है. लिहाज़ा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष अब पाकिस्तान को किसी भी तरह की छूट देने को राज़ी नहीं है. बिजली की दरों पर IMF की शर्तें लागू करने, राजस्व जुटाने के लिए नए-नए कर लगाने और राजकोषीय घाटा कम करने के साथ-साथ पाकिस्तानी रुपए को एक स्तर पर बरक़रार रखने से जुड़ी शर्तें मानने से आर्थिक मोर्चे पर ज़बरदस्त तकलीफ़ें उभरने वाली हैं. 2022 चुनावी साल है, ऐसे में IMF की शर्तों को अमल में लाना सियासी तौर पर ख़ुदकुशी करने के बराबर होगा. हालांकि इन शर्तों पर अमल नहीं करने का अंजाम निश्चित तौर पर दिवालिएपन के तौर पर सामने होगा और अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह से ग्रहण लग जाएगा. [10]
लेकिन ज़रा ठहरिए...IMF का कार्यक्रम सिर्फ़ अल्पकालिक उपाय है. IMF की विस्तारित कोष सुविधा (EFF) से जुड़ा कार्यक्रम जून 2022 में ख़त्म हो रहा है. फ़िलहाल सारी क़वायद अगले 6 महीनों तक वजूद बनाए रखने से जुड़ी है. एक बार IMF का ऋण आ जाने से सऊदी अरब, UAE, चीन और शायद क़तर से भी रकम आने का रास्ता साफ़ हो जाएगा. हालांकि इन तमाम उपायों से वित्त वर्ष 2022 के आख़िर यानी जून 2022 तक के ही हालातों पर क़ाबू हो पाएंगे. ज़ाहिर तौर पर इस वित्त वर्ष की समाप्ति के साथ ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाएगी, और अगले वित्त वर्ष में हालात और ज़्यादा विकट हो जाएंगे. IMF के आकलनों के मुताबिक अगले तीन वर्षों में पाकिस्तान के ऊपर तक़रीबन 75 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर कर्ज़ की देनदारी है. वित्त वर्ष 2024 में उसे क़रीब 25 अरब अमेरिकी डॉलर का ऋण चुकता करना है. इस बीच पाकिस्तान घरेलू और बाहरी मोर्चे पर जो उधार लेता आ रहा है वो भी कर्ज़ का ब्याज़ चुकाने की देनदारियों में जुड़ते चले जाएंगे. अगले वित्त वर्ष की शुरुआत तक पाकिस्तान को IMF के अगले कार्यक्रम (23वां) की शरण में जाना होगा, जो मौजूदा कार्यक्रम से भी ज़्यादा कठिन होगा. शायद, पाकिस्तान के 'दोस्त' भी अगले साल और उसके बाद के वर्षों में उसके लिए अपना ख़ज़ाना खोलने को तैयार नहीं होंगे.
चाहे कुछ भी हो समस्याओं का आकार इतना बड़ा है कि रकम झोंकने की इस तरह की क़वायद अर्थव्यवस्था को महज़ लाइफ़ सपोर्ट पर रखने में ही कामयाब हो सकेगी. इन उपायों से अर्थव्यवस्था को ICU से बाहर लाने (अस्पताल से तो कतई नहीं) में कोई मदद नहीं मिलेगी. सौ बात की एक बात ये है कि पाकिस्तान के पास कर्ज़ से जुड़ी अपनी देनदारियों को पूरा करने का कोई उपाय नहीं है. आसान शब्दों में कहें तो मौजूदा IMF कार्यक्रम से दिवालिएपन को कुछ देर टाला जा सकता है लेकिन इससे पाकिस्तान की समस्याओं का निपटारा नहीं होगा.[11]

निष्कर्ष

ये बात शीशे की तरह साफ़ हो चुकी है कि पाकिस्तान अपने बलबूते कर्ज़ चुकता नहीं कर सकता. पाकिस्तान के पास विकल्प यही है कि वो या तो अभी दिवालिया होने का एलान कर दे या कुछ महीनों बाद ऐसा करे. सियासी तौर पर दोनों ही विकल्प समान रूप से बुरे हैं. इस वक़्त दिवालिएपन को टालने का मतलब है बेहद कड़वी दवा निगलना. भले ही ये क़वायद अर्थव्यवस्था को तबाह ना करे लेकिन मौजूदा सत्ताधारियों की सियासत को बर्बाद ज़रूर कर देगी. जबकि इस वक़्त दिवालिया होने का मतलब है अर्थव्यवस्था और सियासत की तत्काल मौत. पाकिस्तान के लिए दूसरा विकल्प है कर्ज़ के पुनर्गठन और नया कार्यक्रम तय करने की जुगत लगाना. निश्चित तौर पर पाकिस्तानी ये दलील दे सकते हैं कि दुनिया को उनके कर्ज़ को बट्टे खाते में डाल देना चाहिए. हालांकि उन्हें भी ये पता है कि ऐसा नहीं होने वाला.
पाकिस्तान के सामने कर्ज़ चुकाने में नाकाम रहने या ऋण का पुनर्गठन करने का विकल्प है. पहला विकल्प आपात परिस्थितियों में विमान उतारने जैसा है जिसमें किसी को ये पता नहीं होता कि कौन-कौन और क्या-क्या बचेगा, और ना ही ये मालूम होता है कि सलामती से क्या-क्या बाहर निकाला जा सकेगा; जबकि दूसरा विकल्प हार्ड लैंडिंग की तरह है जिसमें गंभीर नुक़सान तो होते हैं लेकिन ज़िंदा बच निकलने की संभावनाएं भी ज़्यादा होती हैं. मौजूदा परिस्थितियों में दूसरा विकल्प मुमकिन तौर पर ज़्यादा सटीक

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 7.421| Peer Reviewed & Referred Journal |

| Volume 10, Issue 1, January 2023 |

लगता है. हालांकि दोनों ही विकल्पों में देनदारियों की उगाही से जुड़ी लंबी और बेहद तकलीफ़देह प्रक्रिया से होकर गुज़रना होगा. इस दौरान पाकिस्तान को बहुपक्षीय संस्थानों के साथ-साथ द्विपक्षीय भागीदारों से भारी-भरकम मदद की दरकार पड़ेगी. यही वो लम्हा है जब अंतरराष्ट्रीय बिरादरी के हाथों में पाकिस्तान को एक सामान्य देश बनाने के लिए ज़ोर लगाने का सुनहरा अवसर दिखाई देता है.

पांच सूत्री योजना[12]

पाकिस्तान को इस मुश्किल से उबारने वाला कोई भी राहत पैकेज पांच सूत्रों की बुनियाद पर तैयार होना चाहिए.

1. अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन (इनमें से कुछ उपायों का ब्योरा ऊपर दिया गया है, हालांकि कई और उपाय किए जाने की दरकार है)
2. पाकिस्तान में सामाजिक, सियासी और प्रशासनिक तौर पर कई तरह के सुधार लाने होंगे. इसके अलावा मानव अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार सुनिश्चित करने होंगे. इस कड़ी में अहमदी समुदाय के साथ-साथ हिंदुओं, सिखों और ईसाई अल्पसंख्यकों का धार्मिक उत्पीड़न बंद करना होगा. पाकिस्तान को नस्ली, मजहबी और भाषाई अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ हर तरह के क़ानूनी और संवैधानिक भेदभाव ख़त्म करने होंगे. साथ ही धार्मिक अल्पसंख्यकों का जबरन धर्मांतरण कराने की क़वायदों पर सख़्ती से अंकुश लगाना होगा.
3. आतंकवाद से तौबा करते हुए हर प्रकार के आंतकी समूहों के ख़िलाफ़ साफ़-साफ़ दिखाई देने वाली और प्रामाणिक कार्रवाई करनी होगी. अच्छे और बुरे तालिबान के बीच फ़र्क़ करने का रिवाज़ बंद करना होगा. स्थानीय या क्षेत्रीय आतंकी समूहों को किसी भी तरह की छूट देने की क़वायद तत्काल रोकनी होगी. इस्लामिक चरमपंथी संगठनों पर नकेल कसनी होगी. बहरहाल, इन उपायों पर कामयाबी से अमल करने के लिए एक ऐसा निगरानी तंत्र स्थापित करना होगा जो ये सुनिश्चित करे कि पाकिस्तान इन प्रतिबद्धताओं से दग़ाबाज़ी ना करे. ग़ौरतलब है कि पाकिस्तान ने FATF के साथ ऐसी ही धोखाधड़ी की थी. FATF द्वारा 'ग्रे लिस्ट' से बाहर कर दिए जाने के बावजूद पाकिस्तान ने AML/CFT नेटवर्कों का अब तक ख़ात्मा नहीं किया है और ना ही आतंकी संगठनों पर किसी तरह की लगाम लगाई है.[13]
4. परमाणु हथियारों के भंडारों में संयम बरतते हुए उनकी तादाद में कटौती लाना. कंट्रोल और कमांड प्रणाली को और पारदर्शी बनाना. पाकिस्तान को अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ने की दरकार नहीं होगी (क्योंकि इससे सौदेबाज़ी की ये क़वायद बिगड़ सकती है) लेकिन उसे कूटनीतिक मोर्चे पर ब्लैकमेलिंग के लिए परमाणु हथियारों को औज़ार की तरह इस्तेमाल में लाने या सौदेबाज़ियों में तुरुप के पत्ते के तौर पर प्रयोग करने की प्रवृति छोड़नी होगी. पाकिस्तान की बेशर्मी देखिए कि जिस वक़्त वो बाक़ी दुनिया से पूरी शिद्दत से बेलआउट पैकेज की गुहार लगा रहा है उसी समय वो दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ परमाणु हथियारों का ज़ख़ीरा भी तैयार कर रहा है.
5. ऊपर की चार शर्तें पूरी किए जाने के एवज़ में पांचवी क़वायद- यानी पाकिस्तान के कर्ज़ों के पुनर्निर्धारण और पुनर्गठन पर सहमति जताई जाएगी. पाकिस्तान का ऋण भार काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और अंतरराष्ट्रीय बिरादरी के उदारता भरे सहायता पैकेज के ज़रिए वहां की अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकी जाएगी. [14]

हक़ीक़त ये है कि कोई भी 24 करोड़ की आबादी वाले मुल्क को कंगाल होते नहीं देखना चाहता, लेकिन पाकिस्तान के कर्ज़ों का बेमियादी रूप से भार उठाने या इसे 'अंतरराष्ट्रीय सिरदर्द' के रूप में बर्दाश्त करने को भी कोई राज़ी नहीं है. पाकिस्तान आज वजूद का संकट झेल रहा है. ये पाकिस्तान और अंतरराष्ट्रीय समुदाय दोनों के लिए बेहतरीन अवसर है. पाकिस्तान को बर्बादी की कगार से वापस लाने और एक सामान्य देश बनाने का ये एक ज़बरदस्त मौक़ा है – एक ऐसा देश जो अपनी जनता के साथ-साथ अपने पड़ोसियों, [15] आसपास के इलाक़ों और विश्व के लिए कोई ख़तरा ना हो. हालांकि इस मंसूबे को साकार करने के लिए निहायत ज़रूरी है कि ऊपर की पांच सूत्री योजना को सटीक क्रम से लागू किया जाए, उसपर पूरी सख़्ती से निगरानी रखी जाए और मज़बूत तरीक़े से पूरी क़वायद को अंजाम दिया जाए. बदले में कुछ ठोस हासिल किए बग़ैर पाकिस्तान को ऐसे ही जाने नहीं दिया जा सकता और ना ही अतीत के वादों के हिसाब से उसे कोई रियायत दी जा सकती है. पाकिस्तानी गाहे-बगाहे और जल्दबाज़ी में ऐसे वादे करते रहते हैं, लेकिन कभी उन वादों की इज़्ज़त नहीं रखते. अगर इस बार भी पाकिस्तान को ऐसी छूट दी गई तो उसे एक सामान्य देश बनाने का बेहतरीन मौक़ा व्यर्थ चला जाएगा. [16]

संदर्भ

1. "Pakistan's population is 207.68m, shows 2017 census result".
2. ↑ Parth R. Chauhan. "An Overview of the Siwalik Acheulian & Reconsidering Its Chronological Relationship with the Soanian – A Theoretical Perspective". Sheffield Graduate Journal of Archaeology. University of Sheffield. मूल से 4 जनवरी 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 मार्च 2014.

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 7.421| Peer Reviewed & Referred Journal |

| Volume 10, Issue 1, January 2023 |

3. ↑ Joseph Needham (1994). A selection from the writings of Joseph Needham. McFarland & Co. पृ॰ 24. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-0-89950-903-7. When the men of Alexander the Great came to Taxila in India in the fourth century BC they found a university there the like of which had not been seen in Greece, a university which taught the three Vedas and the eighteen accomplishments and was still existing when the Chinese pilgrim Fa-Hsien went there about AD 400.
4. ↑ Hermann Kulke; Dietmar Rothermund (2004). A History of India. Routledge. पृ॰ 157. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 0-415-32919-1. In the early centuries the centre of Buddhist scholarship was the University of Taxila.
5. ↑ Balakrishnan Muniapan; Junaid M. Shaikh (2007). "Lessons in corporate governance from Kautilya's Arthashastra in ancient India". World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development 2007. 3 (1): 50–61. डीओआइ:10.1504/WREMSD.2007.012130.
6. ↑ Radha Kumud Mookerji (1951) [reprint 1989]. Ancient Indian Education: Brahmanical and Buddhist (2nd संस्करण). Motilal Banarsidass. पपृ॰ 478–479. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 81-208-0423-6.
7. ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 30 अप्रैल 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 29 अप्रैल 2018.
8. ↑ "Pakistan: The lesser-known histories of an ancient land". मूल से 10 सितंबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 10 सितंबर 2018.
9. ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 11 अक्तूबर 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 29 सितंबर 2011.
10. ↑ Punjabi Musalmans by J.M.Wikeley, Manohar 1991, p4
11. ↑ The Discovery of India by Jawaharlal Nehru, Oxford Uni. Press 1985, p266
12. ↑ "पाकिस्तान में आबादी बढ़ना फायदेमंद या नुकसानदेह?". मूल से 28 अगस्त 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 28 अगस्त 2017.
13. ↑ "जनगणना: पाकिस्तान की जनसंख्या में 57 फीसदी की वृद्धि, अब वहां हैं 20.7 करोड़ लोग". मूल से 26 अगस्त 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 26 अगस्त 2017.
14. ↑ "Enumerating Pakistan". मूल से 28 अगस्त 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 28 अगस्त 2017.
15. ↑ "Pakistan's population reaches 208 million: provisional census results". मूल से 26 अगस्त 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 26 अगस्त 2017.
16. ↑ "Pakistan's 6 th Census - 207 Million People Still Stuck In Malthusian Growth". मूल से 26 अगस्त 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 26 अगस्त 2017.

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| Mobile No: +91-9940572462 | Whatsapp: +91-9940572462 | ijarasem@gmail.com |

www.ijarasem.com